(d) The following amenities are provided to oustees on their rehabilitation:—

(i) A living hut or temporary accommodation is provided.

(ii) A house building loan of Rs. 2,000 per family is allowed.

(iii) Pucca drinking water diggies are provided in the resettlement chaks.

(iv) Dispensaries, Schools, link roads etc. are provided in the new abadies, where considered necessary.

(v) other facilities made available are the taccavi loan for purchase of camel|bullocks, good quality seeds, assistance in getting tractors on hire.

दिल्ली में मल-वहन (सीवेज) व्यवस्था

394. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली की यमुना पार की बस्तियों में मलवहन की व्यवस्था (सीवेज सिस्टम) बनाने के लिये दिल्ली नगर निगम की कोई योजना मिली है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) (1) 0.49 लाख रुपये की अनुमानित लागत की शाहदरा सलेल योजना (पहला भाग) केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरी संगठन द्वारा मंजूर कर दी गई है ।

(2) शाहदरा के कुछ भाग में ट्रंक सीवर्स की व्यवस्था करने के लिए 304.95 लाख रुपये की अनुमानित लागत की एक मलवहन (सीवरेज) योजना की केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरी संगठन तकनीकी छानबीन कर रहा है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्लाट

395. **श्री हर दयाल देवगुण :** क्या निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकार ने 1962 से लेकर अब तक कितनी भूमि का अर्जन किया ;

(ख) इस भूमि का विकास करने के बाद कितने प्लाटों को नीलाम किया अथवा बेचा;

(ग) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली विकास प्राधिकार के कार्य की गति कुछ धीमी है; और

(घ) यदि हां, तो कार्य की गति तीव्र करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) 8,040 एकड़ ।

(ख) 30 अप्रैल , 1967 तक 4,361 रिहायशी तथा 593 औद्योगिक प्लाट ।

(ग) जी हां । भूमि-विकास की प्रगति में प्रमुख गतिरोध हैं :—

(i) पानी की सप्लाई तथा ट्रंक सर्विसज में देरी,

(ii) कुछ प्लाटों के कब्जों के सम्बन्ध में न्यायालय आदेश (कोर्ट इन्जैक्शन) ।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण से कहा गया है कि जहां सम्भव हो वहां पानी की

सफाई तथा मल निकास (सीवेज डिसपोजल) की व्यवस्था, ट्यूबवैलों तथा आक्सीजनरेटेड टैंक के द्वारा अंतरिम रूप से कर लें।

मैसर्स मैकेन्जीज और ओरियन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड

396. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स मैकेन्जीज लिमिटेड और ओरियेन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन ने हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची, हिन्दुस्तान फोटो फिल्म कारपोरेशन, उटकमण्ड और हिन्दुस्तान स्टील, रूरकेला से किसने मूल्य के ठेके प्राप्त किये;

(ख) क्या यह सच है कि इन कम्पनियों ने बहुत अधिक लाभ कमाया परन्तु उन्होंने खातों में बहुत थोड़ी राशि दिखाई;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन दोनों कम्पनियों के खातों की लेखा परीक्षा नहीं की गई है जब कि कम्पनी कानून के अनुसार उनकी जांच होनी चाहिये थी;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा की गई जांच का क्या परिणाम निकला ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) मैकेन्जीज लिमिटेड और ओरियेन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन द्वारा सामेदारी में किये गये ठेकों का मूल्य इस प्रकार है :—

(i) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन 63,84,000 रुपये

(ii) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म कारपोरेशन 69,43,000 रुपये

(iii) हिन्दुस्तान स्टील राउरकेला— करीब 2 करोड़ रुपये

(ख) चूंकि कर-निर्धारण की कार्यवाही अभी चल रही है, इसलिए निश्चित रूप से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका है कि भारी मुनाफे कमाये गये हैं अथवा नहीं ; और कमाये गये मुनाफों को पूरी तरह बहियों में दर्ज किया गया है अथवा नहीं ।

(ग) दोनों कम्पनियों अर्थात् मैकेन्जीज लिमिटेड और ओरिएण्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड के हिसाब-किताब की कम्पनी कानून की व्यवस्था के अनुसार लेखा परीक्षा की गई है ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

(ङ) कर-निर्धारण किये जा रहे हैं ।

All-India Irrigation Commission

397. Shrimati Jyotsna Chanda: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the number of irrigation projects which have been undertaken (major and medium) upto the end of the Third Plan; and

(b) the area of land which will be brought under irrigation when these projects will be completed?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) During the first three Plans, 500 major and medium irrigation schemes were taken up for execution.

(b) On completion, these schemes will create an irrigation potential of 44 million acres.